निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका अहम: सीतारमण

जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की दो दिवसीय बैठक आयोजित

जयपुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख इंजन हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने के मामले में सदस्य देशों के सामने कई समान संरचनात्मक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती केवल पूंजी उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भरोसेमंद, स्थिर और पूर्वानुमेय

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की बैठक को संबोधित किया।

- 'ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास की प्रमुख इंजन, निवेशकों का भरोसा और स्थिरता जरूरी'

माहौल तैयार करने की भी है। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान'द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज'विषय पर आयोजित सेमिनार में सीतारमण ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए। भारत सरकार ने इसी सोच के तहत बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ), हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, क्रेडिट बढ़ाने वाले उपाय, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ परियोजनाओं में तालमेल और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद की है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई लक्षित प्रावधान किए गए हैं। इनमें नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए राष्ट्रीय जलमार्ग और तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के साथ निजी निवेश के नए अवसर तैयार करना है।

सीतारमण ने भारत के बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना इकोसिस्टम को मजबूत किया है। पिछले एक दशक में राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स प्रणालियों, डिजिटल अवसंरचना और ऊर्जा नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकासात्मक वित्त का भविष्य साझेदारी में निहित है। बहुपक्षीय संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों और निजी क्षेत्र की अपनी-अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं। इनके बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाकर विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती है।इससे पहले आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने स्वागत भाषण में कहा कि विकासात्मक वित्त के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने के साथ-साथ मजबूती और दीर्घकालिक स्थिरता भी जरूरी है। सेमिनार में बहुपक्षीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, निजी कंपनियों, थिंक टैंक और अकादमिक जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बाद में निजी पूंजी जुटाने और विकास वित्त से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत पैनल चर्चा भी हुई।

ओपन जेल के कैदी की गोली मारकर हत्या

जयपुर। करणी विहार थाना क्षेत्र के धावास स्थित जानकी विहार इलाके में बुधवार को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ओपन जेल के कैदी मोहन कुमावत (40) की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने मोहन पर तीन राउंड फायर किए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

- बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने तीन राउंड फायर किए
- जेल लौटते समय धावास के जानकी विहार में वारदात

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। सामने से मौका मिलते ही उन्होंने मोहन को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर करणी विहार के साथ भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मोहन कुमावत 2018 में मोती डूंगरी इलाके में महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और उसे सजा हुई थी। वर्तमान में वह सांगानेर स्थित ओपन जेल में बंद था। बुधवार को वह जेल लौट रहा था। इसी दौरान धावास के जानकी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर उसे निशाना बनाया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री सीएलजी सदस्यों से आज संवाद करेंगे

जयपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द्र और पुलिस-जन सहभागिता को मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) को प्रभावी बनाने की पहल शुरू की है। इसके तहत गुरुवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशभर के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर रेंज के सभी पुलिस थानों के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों को बिड़ला ऑडिटोरियम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण व जुड़े मुकदमों की जानकारी मांगी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला की जनहित याचिका सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए द्रववती नदी को दूषित बताया और साथ ही कहा की शहर में इंदौर के मुकाबले गंदगी अधिक है

- अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अलंकृता शर्मा और शोभित तिवाड़ी ने अदलात को कहा कि उनकी ओर से गत फरवरी माह में रिपोर्ट देकर कई कमियों को उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यदि रिपोर्ट में कोई कमी है तो उसे बताए, वरना रिपोर्ट पर कार्रवाई करें। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर अपना रिस्पॉन्स पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 6 माह बाद भी सरकार समय ही मांग रही है। ऐसे में सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता पीएन मैंदोला ने उपस्थित होकर कहा कि नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरों पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए कईयों का नियमन भी कर रहा है। इस पर जेडीए के अधिवक्ता ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोग विभिन्न अदालतों में जाकर स्थगन आदेश ले आते हैं। इस पर खंडपीठ ने जेडीए को यहां के अतिक्रमण और मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रिस्पॉन्स पेश करने के आदेश दिए हैं।

दो तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत हरमाड़ा और मानसरोवर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

192 गांवों में जल्द बनेंगे अटल प्रगति पथ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रदेश में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गांवों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में 5 हजार से अधिक आबादी के शेष 192 गांवों में भी अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 381.91 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से 28 जिलों के 192 गांवों एवं आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हो सकेंगे।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का प्रत्येक गांव और आबादी क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़े और विकास का लाभ अंतिम छोर तक सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा है कि सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली आधारभूत कड़ी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से संवाद किया

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान कहा कि युवा मतदाता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपने मताधिकार के महत्व से परिचित कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर जन-जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सिंह राजकीय महाविद्यालय, जयपुर में बुधवार को आयोजित युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद सहित अनेक महान व्यक्तित्वों का योगदान रहा है। आज के युवाओं को उनके विचारों और देश के प्रति योगदान से प्रेरणा लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझें तथा किसी भी विषय पर अपना मत बनाने से पहले तथ्यात्मक जानकारी का अध्ययन करें।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में अध्ययन और विश्लेषण की आदत विकसित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से चिन्तन, मनन, विवेचन और विश्लेषण से अपना मत तय करने का आव्हान किया। निर्वाचन आयुक्त ने

निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

कहा कि युवा मतदाताओं के आवश्यक रूप से अपना मतदाता पहचान-पत्र बनवाना चाहिये और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिये। साथ ही अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों में जनता को स्वयं जागरुक होकर निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के आधार जन प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिये।कार्यक्रम में महाविद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब ( ) की ओर से वर्षभर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। ईएलसी प्रभारी प्रो. गोविन्द शरण शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में युवाओं को चुनावी प्रक्रिया तथा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के प्रति जागरूक करने के लिए निबंध, कविता पाठ, पोस्टर एवं रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

पशुपालन विभाग में 113 कार्मिकों को मिला पदोन्नित का तोहफा

जयपुर। पशुपालन विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विभाग ने मंत्रालयिक संवर्ग की सभी श्रेणियों की पदोन्नित प्रक्रिया वर्ष 2025-26 तक पूर्ण कर दी है। विभाग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक के पश्चात विभिन्न पदों पर कुल 113 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है जिनमें संस्थापन अधिकारी के 05, प्रशासनिक अधिकारी के 16, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 38, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 34 तथा वरिष्ठ सहायक के 20 पद हैं।विभाग की ओर से पदोन्नित प्रक्रिया को निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से संपन्न किया गया है। इससे मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को उनकी योग्यता, अनुभव एवं सेवा अवधि के अनुरूप पदोन्नित का लाभ प्राप्त हुआ है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीणा ने कहा कि मंत्रालयिक संवर्ग के सभी वर्गों की पदोन्नित वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पदोन्नित प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए गए। उन्होंने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्मिक किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

दुष्कर्म आरोपी समेत हुक्का बार संचालक गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को वारदात के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोपालपुरा मोड़ स्थित एक रेस्तरां में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर दबिश देकर दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर जब्त किए। डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। एडीसीपी पारस मल जैन और एसीपी मालवीय नगर विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामधन ढोबाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता और लगातार प्रयासों के बाद अंकित कुमार (26) निवासी निमभोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया।दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने गोपालपुरा मोड़ स्थित फिन रेस्तरां कैफे पर दबिश दी। जांच के दौरान कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होना पाया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर बरामद किए।

राज्य में ''2047 तक सभी के लिए बीमा'' के लिए तैयारियां शुरू

जयपुर। '2047 तक सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रशासनिक तंत्र ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सम्बंध में बुधवार को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) चैयरमैन श्री अजय सेठ के बीच शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में वित्त (व्यय) सचिव डॉ. टीना सोनी भी उपस्थित रही।

मुख्य सचिव और आईआरडीएआई चैयरमैन के बीच रोडमेप के बारे में चर्चा हुई।

बैठक में असंगठित और वंचित वर्गों के बीच बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों ने स्वास्थ्य दावों के इंटरऑपरेबिलिटी, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए आरजीएचएस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय के साथ एकीकृत करने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया। राज्य भर में वाणिज्यिक वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज अनिवार्य करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव और आईआरडीएआई अध्यक्ष ने मोटर वाहन दुर्घटना दावों के लम्बित मामलों का लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित निस्तारण करने की सम्भावना पर विचार किया जिससे दावेदारों को समय पर राहत मिल सके। बैठक में लिए निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य बीमा एवं साधारण प्रावधायी निधि विभाग शीघ्र ही सम्बंधित विभागों, एजेन्सियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की बैठक आयोजित करेगा। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष , राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईपीएफ निदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, अस्पताल संघों के प्रतिनिधि और प्रमुख बीमा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

महारानी कॉलेज में तीन दिवसीय आनंदम् कार्यशाला का आयोजन

जयपुर। महारानी कॉलेज में 10 से 12 अगस्त 2026 तक हार्टफुलनेस संगठन के सहयोग से प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के मूल्य-वर्धित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय पर तीन दिवसीय आनंदम् कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में जीवन कौशल, तनाव प्रबंधन, सजगता, आत्म-जागरूकता तथा भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना रहा। तीनों दिवस विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामना करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों एवं गतिविधियों से परिचित कराया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस में हार्टफुलनेस तकनीकों द्वारा जीवन कौशल संवर्धन विषय पर सत्र आयोजित किया गया।

नवाचारों के साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास को मिले प्राथमिकता : एसीएस

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों, नवाचारों एवं कार्ययोजना पर मंथन

जयपुर। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में पीरामल फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल, सीईओ आदित्य नटराज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन एवं सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल के साथ राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों, नवाचारों, मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं भावी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल, रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में यादव ने प्रदेश में संचालित विभिन्न शैक्षिणक योजनाओं, सरकारी विद्यालयों एवं शिक्षा कार्मिकों से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 649 पीएमविद्यालयों की तरह सीएम राइज

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में भावी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की।

- एआई, डिजिटल तकनीक से स्मार्ट शिक्षा और मॉडल स्कूलों से सशक्त होगी राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था

में 400 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा सेतु कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसके माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिणक आवश्यकताओं एवं विद्यालयी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

एसीएस ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएं। उन्होंने विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का विस्तार करने तथा दूरस्थ एवं छोटे गांवों के विद्यालयों तक इनका लाभ पहुंचाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में विद्यार्थियों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संस्थागत स्तर पर कार्यक्रम संचालित करने, ड्रॉपआउट रोकने, नियमित उपस्थिति बढ़ाने तथा कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। चयनित सरकारी विद्यालयों को बेहतर सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हुए मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

पीरामल फाउंडेशन के संस्थापक अजय पीरामल ने संस्था द्वारा राजस्थान में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया तथा चर्चा एवं सुझावों के अनुरूप सहयोग को और बढ़ाने का आश्वासन दिया।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं, जेंडर, हाईजीन, आधारभूत संरचना, राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा विद्यार्थियों के शैक्षिणक विकास के साथ उनके समग्र विकास, कौशल एवं रोजगार क्षमता पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : जोराराम कुमावत

जयपुर। पशुपालन, डेयरी गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में पशुपालन विभाग एवं डेयरी की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की गई।

कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखकर की गई हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक घोषणा की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति से

- बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की

संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं, नवीन पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा उपकेंद्रों, मोबाइल वेटनरी यूनिट, पशुधन विकास, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण पशुपालन अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उनका शीघ्र समाधान कर कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए। उन्होंने सभी स्तर के चिकित्सा संस्थाओं के पट्टे जल्द से जल्द हासिल करने पर बल देते हुए कहा कि हर संस्थान के पास अपना भवन होना चाहिए जिससे पशुओं को बेहतर चिकित्सा मिल सके। कुमावत ने भेड़ ऊन विभाग की जमीन को भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत शामिल करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मंत्री कुमावत ने डेयरी की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन उत्पादों की मांग अधिक है उनका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने बस्सी में स्थित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन इकाई की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाएं केवल घोषणा मात्र नहीं हैं इससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों का सशक्तीकरण होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए इन घोषणाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।